

अयोध्या : मुसलिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सोमवार को एक मुसलिम पक्षकार ने याचिका दायर की और कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का निर्देश देने पर ही संपूर्ण न्याय हो सकता है।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोहोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि राम लला को सौंपने और मस्जिद निर्माण के लिए उग्र सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ का भूखंड आर्बिट कर देने का केंद्र को निर्देश दिया था।

हालांकि, संविधान पीठ के इस फैसले को उग्र सुन्नी सेंट्रल

फैसला सबूतों और तर्क पर आधारित नहीं : मदनी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

प्रमुख मुसलिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशाद मदनी ने सोमवार को दावा किया कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला 'बहुसंख्यकवाद और भीड़तंत्र' को न्यायसंगत ठहराता है। उन्होंने कहा कि जमीयत इसलिए न्यायालय गई है, क्योंकि अयोध्या



बाकी पेज 8 पर

महिला सुरक्षा : देश भर में आक्रोश, संसद में गूंज

सरकार कठोरतम कानून बनाने के लिए तैयार

लोकसभा सदस्यों की भावना से सहमति जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एक युवती के साथ बलात्कार और उसकी निर्भय हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सदन में कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी तो सरकार इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा- इससे अधिक अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता है। सभी शर्मसार और आहत हैं। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद इसी सदन में कठोर कानून बना था लेकिन उसके बाद भी इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है और ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा देने पर सदन में जो सहमति बनती है, उसके आधार पर सरकार प्रावधान लाने को तैयार है।



बाकी पेज 8 पर

बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से मिले सजा : जया बच्चन

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और उसे जलाकर मार डालने की घटना की सोमवार को अधिकतर राज्यसभा सदस्यों ने निंदा की। ज्यादातर सदस्यों ने ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई कर दोषियों को मौत की सजा देने और सामाजिक बदलाव के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की मांग की।



बाकी पेज 8 पर

समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने कहा कि बलात्कार के दोषियों के साथ किसी तरह की

दोषियों की ओर से आगे अपील करने के चलन की समीक्षा की जरूरत : वैकेया

राज्यसभा के सभापति एम वैकेया नायडू ने ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों की ओर से उच्च अदालतों में अपील करने और दया याचिका दायर करने की अनुमति देने के चलन की समीक्षा करने की जरूरत पर बल दिया है। सदस्यों के अभी बात रखने के बाद सभापति नायडू ने कहा कि महिलाओं के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों में निचली अदालतों में सजा सुनाए जाने के बाद दोषी न केवल आगे की अदालतों में अपील करते हैं बल्कि वह माफ़ी के लिए क्षमा याचिका भी देते हैं। 'इस चलन की समीक्षा की जानी चाहिए।' नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फ़ास्ट ट्रैक अदालतें ही एकमात्र समाधान हैं लेकिन अपील दर अपील का सिस्टमिला भी चलता रहता है।

लोग सड़कों पर उतरे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार-हत्या के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को दिल्ली सहित देश में कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे। छात्र संगठन



बाकी पेज 8 पर

देवेन्द्र फडणवीस ने खारिज किया अनंत हेगड़े का दावा

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस की अगुआई वाली अल्पकालिक सरकार के गठन को लेकर एक बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कांग्रेस व शिवसेना ने उनके बयान को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है तो खुद फडणवीस ने हेगड़े के बयान को खारिज कर दिया है।



बाकी पेज 8 पर

'इस तरह कोई कोष नहीं लौटाया जाता'

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने हेगड़े के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने उस बयान को पूरी तरह निराधार बताया जिसमें बहुमत नहीं होने के बावजूद 40 हजार करोड़ की केंद्रीय निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। फडणवीस ने नागपुर में कहा- यह बिलकुल गलत है और मैं इस पूरी तरह खारिज करता हूँ। केंद्र सरकार की एक कंपनी बुलेट ट्रेन परियोजना ला रही है, जहां महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भूमि अधिग्रहण तक सीमित है। केंद्र ने न ही किसी कोष की मांग की और न ही महाराष्ट्र सरकार ने उसे वापस किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया। जो लोग केंद्र और राज्य सरकार की लेखांकन प्रणाली को समझते हैं उन्हें पता होगा कि इस तरह कोई कोष लौटाया नहीं जाता।



बाकी पेज 8 पर

तमिलनाडु के मेट्टुपलायम में वर्षा का कहर

भारी बारिश, दीवार गिरने से 17 की मौत

कोयंबटूर/इरोड (तमिलनाडु) 2 दिसंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के मेट्टुपलायम में भारी बारिश के कारण एक दीवार कई दूसरे मकानों पर गिर गई जिससे 10 महिलाओं और दो बच्चों सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर तमिलनाडु के पश्चिमी जिले इरोड में भवानी नदी के तटों के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी निजी परिसर की 15 फुट ऊंची दीवार सुबह करीब पांच बजे नजदीकी घरों की छतों पर गिर गई, जिससे घरों में सो रहे कई लोग अंदर ही दब गए। दमकल एवं बचाव सेवा कर्मियों ने स्थानीय लोगों और पुलिस की

पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी निजी परिसर की 15 फुट ऊंची दीवार सुबह करीब पांच बजे नजदीकी घरों की छतों पर गिर गई, जिससे घरों में सो रहे कई लोग अंदर ही दब गए।



इरोड में भवानी नदी के तटों के पास रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी

मदद से मलबे से शव बाहर निकाले। बचाव अभियान अभी जारी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने घटना पर शोक जताते हुए मारे गए लोगों के परिवारों के लिए राज्य आपदा राहत कोष से चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा भी की। कोयंबटूर जिला कलक्टर के राजामणि और पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार भी घटना

बाकी पेज 8 पर

भारत की जवाबी कार्रवाई में चार पाक फौजी ठेर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

पाकिस्तानी सेना ने रविवार को पुंछ जिले के करबा और शाहपुर सेक्टर में संघर्षविराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने यह नापाक हरकत शाम करीब चार बजे की। इस नापाक हरकत में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। नियंत्रण रेखा के पार राखचिकरी और रावलकोट सेक्टरों में पाकिस्तान

कैग की रिपोर्ट : दस साल में सबसे खराब रहा परिचालन अनुपात

रेलवे ने 100 रुपए कमाने के लिए खर्चे 98.44 रुपए

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय रेल का परिचालन अनुपात (ओआर) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसद दर्ज किया गया जो पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब है। यह बात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट से सामने आई है। इसके साथ ही कैग ने सिफारिश की है कि रेलवे को आंतरिक राज्य बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सके।

2017-18 के वित्तीय वर्ष में सौ रुपए कमाने के लिए खर्च किए 98.44 रुपए कैग ने रेलवे को आंतरिक राज्य बढ़ाने के उपाय करने की सिफारिश की है ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके।



रेलवे में इस परिचालन अनुपात (ओआर) का तात्पर्य यह है कि रेलवे ने 100 रुपए कमाने के लिए 98.44 रुपए व्यय किए। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसद रहने का मुख्य कारण संचालन व्यय में उच्च वृद्धि है।

इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2008-09 में रेलवे का परिचालन अनुपात 90.48 फीसद था जो 2009-10 में 95.28 फीसद, 2010-11 में 94.59 फीसद, 2011-12 में 94.85 फीसद, 2012-13 में 90.19 फीसद, 2013-14 में 93.6 फीसद, 2014-15 में 91.25 फीसद, 2015-16 में 90.49 फीसद, 2016-17 में 96.5 फीसद और 2017-18 में 98.44 फीसद दर्ज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेल का कुल व्यय

बाकी पेज 8 पर

दरअसल



सड़क हादसों के आंकड़े पर नितिन गडकरी ने जताया अफसोस

कबूलनामा

हादसों में मरने वालों की संख्या 0.2 फीसद बढ़ गई है

कानून तो हुआ सख्त पर घटी नहीं हादसों में मरने वालों की संख्या

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को माना कि मोटर वाहन कानून को सख्ती के साथ लागू किए जाने के बावजूद देश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि पिछले साल जनवरी से सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर तक सड़क हादसों में 2.2 फीसद की कमी आई है लेकिन इन हादसों में मरने वालों की संख्या 0.2 फीसद बढ़ गई है।

पूरक प्रश्नों के जवाब में गडकरी ने उच्च सदन को बताया, 'सड़क हादसों के आज आंकड़े देखने के बाद मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अभी भी सड़क हादसों और मरने वालों की संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है।' गडकरी ने

सड़क हादसों के आज आंकड़े देखने के बाद मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अभी भी सड़क हादसों और मरने वालों की संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, बोले गडकरी। **संशोधित** मोटर वाहन कानून इस साल एक सितंबर से लागू हुआ था। **गडकरी** ने तमिलनाडु में सड़क हादसों में 29 फीसद कमी आने का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून को कारगर तरीके से लागू करने के लिए तमिलनाडु का मॉडल अनुकरणीय है।



बाकी पेज 8 पर

इसके लिए सड़क इंजीनियरिंग संबंधी खामियों को प्रमुख वजह बताते हुए कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार और सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट की पहचान कर इन्हें दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सात सात

हजार करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक (एडीबी) को सौंपी है। उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में भारी इजाफे का उद्देश्य राज्यस

प्राप्त करना नहीं बल्कि 25 साल पहले निर्धारित जुर्माना राशि को समायानुकूल बनाते हुए लोगों को कानून के पालन के प्रति जागरूक बनाता है। गौरतलब है कि संशोधित मोटर वाहन कानून इस साल एक सितंबर से लागू हुआ था।

गडकरी ने तमिलनाडु में सड़क हादसों में 29 प्रतिशत कमी आने का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून को कारगर तरीके से लागू करने के लिए तमिलनाडु का मॉडल अनुकरणीय है और अन्य राज्यों से भी इसे अपनाने का अनुरोध किया गया है। वाहन की कीमत से अधिक जुर्माना वसूलने के प्रावधानों पर सवाल खड़े वाले एक पूरक प्रश्न के जवाब में गडकरी ने कहा कि संशोधित कानून में जुर्माना संबंधी प्रावधानों को समवर्ती सूची के तहत निर्धारित किया गया है इसलिए राज्य अपनी संहलियत से जुर्माने की राशि का निर्धारण कर सकते हैं।



बाकी पेज 8 पर

